

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि०आ०-सा०नि०)अनु०-7
संख्या: 204/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक: 21 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2008 के अध्याय-4 में सेवाओं की अधिप्राप्ति विषयक नियम-58 में राज्य के दो संयुक्त उपक्रमों के लिए शिथिलीकरण।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2008 के अध्याय-4 में सेवाओं की अधिप्राप्ति विषयक नियम-58 में विशेष परिस्थितियों में एकल स्रोत के आधार पर परामर्शी का व्ययन रु० 10 लाख तक की लागत के प्रकरणों के लिए संबंधित विभाग द्वारा किये जाने तथा रु० 10 लाख से अधिक लागत के प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने का प्राविधान है।

उपर्युक्त नियम को शिथिल करने विषयक उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी(यूडैक) के पत्र संख्या यू-डीइसी/08-09/575 दिनांक 30 मार्च, 2009 एवं उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के पत्र संख्या यूआईपीसी/पीकेजी/39 दिनांक 7 मई, 2009 के सन्दर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनाओं के लिए कन्सलटेन्ट व्ययन करने की प्रक्रिया में परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब से बचने तथा सम्प्रति कन्सलटेन्ट के व्ययन हेतु टेन्डर प्रक्रिया हेतु पर्याप्त कंपैसिटी बिल्डिंग न होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के दो संयुक्त उपक्रमों-उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी(यूडैक) तथा उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड(यूआईपीसी) से परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रैक्वोरमेंट) नियमावली, 2008 के अध्याय-4 में सेवाओं की अधिप्राप्ति के नियम-58 में प्रैक्वोरमेंट नियमावली के नियम-72(4) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में शिथिलीकरण करते हुए रु० 10,00,000(रु० दस लाख मात्र) तक की सीमा को बढ़ाकर रु० 25,00,000(रु० पच्चीस लाख मात्र) तक की कन्सलटेन्सी संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य सरकार के उक्त दो संयुक्त उपक्रमों से बिना टेन्डर प्रक्रिया से लिए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- अधिप्राप्ति नियमावली के नियम-58 में उक्त शिथिलीकरण केवल राज्य सरकार के उक्त दो संयुक्त उपक्रमों के लिए होगा तथा अन्य संस्थाओं/उपक्रमों आदि के लिए नियम-58 में विहित वर्तमान व्यवस्था रु० 10 लाख यथावत रहेगी। उक्त संयुक्त उपक्रमों से ली जाने वाली कन्सलटेन्सी की कारस्ट की युक्तियुक्तता(Reasonableness) सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग का होगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: 20^१/xxvii(7)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
7. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
8. मुख्य कार्याकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी(यूडिक) ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
11. गार्ड फाईल ।

आज्ञा है

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।